सरकारी कार्यालयों में बायोमैट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य

सीएम ने नए वर्ष की प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को लेकर पहली बार अफसरों के साथ बैठक की

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 7 जनवरी. प्रदेश में कोविड काल से ही सरकारी कार्यालयों में 5 दिवसीय सप्ताह की व्यवस्था लागू है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए बाद में सरकारी कार्यालयों के खुलने का समय प्रात: 10 से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया था.

लेकिन दूसरे कार्यालय तो छोड़ दें, मंत्रालय में ही अधिकारी-कर्मचारी तय समय पर नहीं पहुंचते. लिहाजा अब आने वाले दिनों में इस मामले में सख्ती हो सकती है और सरकारी कार्यालय में बायोमेट्रिक अटेंडेस को अनिवार्य किया जा सकता है.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को इस संबंध में संकेत दिये हैं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंत्रालय में बड़ी बैठक की. बैठक में वर्ष 2026 के लिए शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं, निर्माण परियोजनाओं और अन्य कार्यक्रमों के समयबद्ध क्रियान्वयन के संबंध में विचार-विमर्श किया गया, बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना के

साथ ही सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव सहित पुलिस तथा भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. इस दौरान बैठक में सीएम ने कहा कि कोविड काल से प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में 5 दिवसीय सप्ताह की व्यवस्था लागू है. इस अवधारणा को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए कार्यालयीन समय को बढ़ाना और सभी के द्वारा उसका अनुसरण आवश्यक है. यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में प्रात: 10 बजे से कार्य आरंभ हो, इसके लिए बायोमेट्रिक सहित अन्य तकनीकी प्रणालियों का सहारा लिया जाए. इससे अनुशासन के साथ कार्य निष्पादन में भी सुधार होगा.

मिशन मोड पर काम करना होगा

बैठक में सीएम ने अफसरों को नसीहत देते हुए कहा कि प्रदेश में विकास और उन्नति को अधिक गति देने के लिए मिशन मोड में काम करना होगा. प्रदेश में विकास गतिविधियों का तेजी से क्रियान्वयन हो और जनकल्याणकारी योजनाओं का सभी पात्र व्यक्तियों को सुगमता से लाभ मिले यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए जवाबदेही तय करने की व्यवस्था को सशक्त करना होगा . वर्ष 2026 किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा. हमारा लक्ष्य समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 12 जनवरी से 31 मार्च संकल्प से समाधान अभियान-वन आरंभ किया जा रहा है. यह अभियान 106 प्रमुख हितग्राहीमूलक योजनाओं पर केंद्रित होगा. जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि शिविरों में प्राप्त समस्त आवेदनों का अंतिम निराकरण 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से हो.

स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट गठित

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 7 जनवरी. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कमाण्ड क्षेत्र विकास का आधुनिकीकरण एमसीएडी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन ने सचिव, जल संसाधन की अध्यक्षता में राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई स्टेट प्रोजेक्ट मेनेजमेंट यूनिट एसपीएमयू का गठन किया है.

समिति में आयुक्त कमाण्ड क्षेत्र विकास जल संसाधन, प्रमुख अभियंता जल संसाधन, सदस्य अभियांत्रिकी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, योजना से संबंधित मुख्य अभियंता जल संसाधन/एनवीडीए, संचालक कृषि एवं किसान कल्याण, संचालक उद्यानिकी, संचालक हाइड्रोलॉजी बोधी, जल संसाधन, संचालक सहभागिता सिंचाई प्रबंधन, जल संसाधन, योजना से संबंधित अधीक्षण यंत्री जल संसाधन/ एन.वी.डी.ए, योजना से संबंधित कार्यपालन यंत्री जल संसाधन/ एनवीडीए सदस्य होंगे. मुख्य अभियंता बोधी जल संसाधन को सदस्य सचिव नामित किया गया है.

राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई के दायित्व अनुसार मॉडल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार सिंचाई के लिए उपलब्ध जल का बेहतर उपयोग करने के लिए जल विज्ञान हाइड्रोलॉजी, इंजीनियरिंग तथा कृषि विशेषज्ञों के सहयोग से रूप रेखा तैयार करवाने तथा कार्यान्वयन करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशन को लागू किया जाएगा.

पानी में हैजा बैक्टीरिया मिलने का दावा

20 की मौत, 1 हजार से अधिक बीमार

विशेष संवाददाता

भोपाल, 7 जनवरी. इंदौर में कथित रूप से दूषित पेयजल के सेवन से 20 लोगों की मौत और 1,000 से अधिक नागरिकों के गंभीर रूप से बीमार होने के मामले में कांग्रेस ने भाजपा-नेतृत्व वाली मध्यप्रदेश सरकार पर बोला हमला.

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष डॉ. मुकेश नायक ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए इस घटना को 'बेहद चौंकाने वाली' बताया और सरकार पर असंवेदनशीलता तथा जवाबदेही तय करने में पूरी तरह

विफल रहने का सरकार पर आरोप लगाया. डॉ. नायक ने कहा कि पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हाल ही में प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, जहां पीड़ितों ने सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी त्रासदी के बावजूद अब तक केवल चार परिवारों को ही दो लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है.

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इंदौर के प्रभारी मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री होने के बावजूद दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. पार्टी ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कथित रूप से पत्रकारों के साथ अभद्रता की भी निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान बताया. और आगे चिंता जताते हुए कांग्रेस ने दावा किया कि पानी में हैजा बैक्टीरिया पाया गया है और सवाल उठाया कि क्या इसकी जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी गई. पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस ने 11 जनवरी को इंदौर में राज्य स्तरीय 'न्याय यात्रा' निकालने की घोषणा की है.

87 किलो डोडाचूरा जब्त

इंदौर,7 जनवरी. नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन ईगल क्लॉ के तहत तेजाजीनगर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए पंजाब से इंदौर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है.

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 87 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 35 लाख रुपये बताई जा रही है. साथ ही तस्करी में प्रयुक्त ट्रक को भी जब्त किया गया है. तेजाजीनगर थाना प्रभारी देवेन्द्र मरकाम ने बताया कि यह कार्रवाई एबी रोड बायपास स्थित आउटर कॉलोनी क्षेत्र में नियमित चेकिंग के दौरान की गई.

इंदौर उज्जैन के बीच मेट्रो का प्रस्ताव

48 किमी की इंदौर उज्जैन मेट्रो

05 साल में पूरी होगी योजना

इंदौर,7 जनवरी. इंदौर और उज्जैन के बीच मेट्रो रेल चलाने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर मध्यप्रदेश मेट्रो को प्रस्तुत कर दी गई है.

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा तैयार इस डीपीआर के अनुसार, योजना की कुल लागत लगभग 12 हजार करोड़ रुपए आएगी और इसे 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. उक्त योजना में उज्जैन शहर में 5

किलोमीटर अंडर ग्राउंड लाइन डाली जाएगी, जबकि शेष मार्ग एलिवेटेड होगा. इंदौर और उज्जैन के बीच 48 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन प्रस्तावित है, जिसमें 11 स्टेशन शामिल होंगे. पहले इस योजना की लागत 10 हजार करोड़ रुपए अनुमानित थी, लेकिन उज्जैन शहर में अंडर ग्राउंड लाइन के कारण खर्च बढ़कर 12 हजार करोड़ रुपए हुआ. इस योजना को बजट में पहले मंजूरी देने पर चर्चा हो रही है ताकि केंद्र सरकार के आम बजट में इसके लिए राशि का प्रावधान किया जा सके. योजना को केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश सरकार टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगी. मध्यप्रदेश सरकार की मंशा है कि मेट्रो परियोजना को उज्जैन में सिंहस्थ के पहले पूरा किया जाए.

एक नजर में

प्रस्तावित लागत: 12 हजार करोड़ रुपए
कुल लंबाई: 48 किलोमीटर
उज्जैन में अंडर ग्राउंड लाइन: 5 किलोमीटर
स्टेशन संख्या: 11
कार्य पूरा करने का लक्ष्य: 5 साल

एक नजर में

प्रदेश में 43 लाख 17 हजार मीट्रिक टन धान खरीदी

भोपाल. प्रदेश में अभी तक 6 लाख 56 हजार 875 किसानों से 43 लाख 17 हजार 504 मीट्रिक टन धान की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है. धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रूपये प्रति क्विंटल है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि धान विक्रय के लिए किसान 13 जनवरी तक स्लॉट बुक करा सकते हैं. उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि निर्धारित समय पर स्लॉट बुक जरूर करा लें. धान की खरीदी 20 जनवरी तक की जायेगी. किसानों को 6791 करोड़ रूपये से अधिक राशि का भुगतान भी किया जा चुका है.

आर्मी अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट से कराया मुक्त

उज्जैन। आर्मी से सेवानिवृत अधिकारी और उनकी पत्नी को मुंबई पुलिस बनकर कुछ बदमाशों ने डिजिटल अरेस्ट कर लिया था। सेवानिवृत अधिकारी बदमाशों को राशि ट्रांसफर करने के लिए बैंक पहुंचे थे, लेकिन बैंक के सीनियर एसोसिएट की समझदारी से पुलिस ने सेवानिवृत्त आर्मी अधिकारी को धोखाधड़ी से बचा लिया। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि बुधवार दोपहर को लेकोड़ा में रहने वाले आर्मी से सेवानिवृत लेफ्टिनेंट नई सड़क स्थित एसबीआई बैंक पहुंचे थे और अपने खाते से 3 लाख का आरटीजीएस करने की बात कहने लगे।

घने कोहरे से उड़ानों की रफ्तार प्रभावित

पांचवें दिन भी एयर ट्रैफिक प्रभावित

10 से ज्यादा फ्लाइट लेट, चेन्नई की उड़ान रद्द

200 मीटर तक गिरी इंदौर एयरपोर्ट पर दृश्यता

इंदौर, 7 जनवरी. खराब मौसम और घने कोहरे का असर बुधवार को लगातार पांचवें दिन देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर देखने को मिला.

तड़के से ही एयरपोर्ट क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहा, जिससे

दृश्यता घटकर करीब 200 मीटर रह गई. कम दृश्यता के चलते सुबह के समय उड़ान संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ. 10 से अधिक उड़ानों को देरी से संचालित करना पड़ा, वहीं इंडिगो एयरलाइंस ने चेन्नई जाने वाली अपनी एक उड़ान को निरस्त कर दिया. एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक सुबह 6:30 से 9:30 बजे के बीच उड़ानों की समयबद्धता पूरी तरह बिगड़ी रही. इसी स्लॉट में टेकऑफ और लैंडिंग सबसे ज्यादा प्रभावित हुई. घने कोहरे के कारण पायलटों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ी, जिससे एक के बाद एक उड़ानों में देरी होती चली गई.

सुबह की फ्लाइट से सफर करने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ा, वहीं कई यात्रियों की आगे की कनेक्टिंग फ्लाइट भी छूट गई. इधर, इंडिगो द्वारा चेन्नई की उड़ान रद्द किए जाने से यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ गई. एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. मौसम में सुधार के बाद ही उड़ानों का संचालन किया और हालात सामान्य करने के प्रयास किए.

मध्यप्रदेश स्टार्टअप समिट 11 से होगी

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के 'विकसित एम.पी. @2047' विज़न को साकार करने और प्रदेश के स्टार्ट-अप इको-सिस्टम को अगले स्तर तक ले जाने के उद्देश्य से 11 एवं 12 जनवरी 2026 को रवींद्र भवन, भोपाल में मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है. सोमवार 12 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समिट में सहभागिता करेंगे. समिट में मध्यप्रदेश सहित देशभर से स्टार्ट-अप्स, निवेशक, इनक्यूबेटर्स, उद्योग प्रतिनिधि, शैक्षणिक संस्थान एवं अन्य हितधारक शामिल होंगे. यह आयोजन स्टार्ट-अप्स को निवेश, नेटवर्किंग, नीति संवाद एवं नवाचार प्रदर्शन के लिए एक प्रभावी मंच उपलब्ध कराएगा.

पेज एक का शेष

विपक्ष तथ्यात्मक बात नहीं करता...

मनरेगा अधिनियम में रोजगार की यह गारंटी मात्र 100 दिन की थी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वीबी जी-राम-जी योजना देश के सभी गांवों की तस्वीर बदल देगी. यह गरीबों, खेतीहर मजदूरों, किसानों सभी के लिए बेहद लाभकारी है. इस योजना से गांवों के विकास को भी मजबूती मिलेगी. मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वे प्रदेश के विकास के लिये सर्वदलीय बैठक बुलाने वाले हैं, जिससे कि सभी के अनुभव का लाभ प्रदेश को मिले, विषय विशेषज्ञों को भी बुलाया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पहले किसानों को कृषि से जुड़े कामों के लिए श्रमिक ही नहीं मिलते थे, पर वीबी जी-राम-जी योजना में कृषि के व्यस्ततम समय, विशेषकर बुवाई और कटाई के समय पर्याप्त मात्रा में कृषि श्रमिकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है. इस अधिनियम में राज्यों को एक वित्त वर्ष में कुल 60 दिन की अवधि अधिसूचित करने का प्रावधान किया गया है, बीज बुवाई एवं फसल कटाई की व्यस्ततम समयावधि को भी रोजगार उपलब्ध कराने की अवधि में शामिल किया जा सकेगा. प्रावधान के अनुसार इस अवधि में अधिनियम के तहत शामिल अन्य कार्य नहीं किए जाएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में पहले 6 प्रतिशत प्रशासनिक अमला तैनात किया गया था. विकसित भारत जी-राम-जी योजना में इस कार्यकारी अमले की तादाद बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दी गई है. इससे योजना के क्रियान्वयन में जवाबदेहिता बढ़ेगी, साथ ही सभी गतिविधियों को पूरी पारदर्शिता से अंजाम दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार तय मानकों के आधार पर देश के हर राज्य को एक निश्चित राशि भी देगी. अधिनियम में ग्रामीण आजीविका निर्माण के स्थाई स्रोत विकसित करने पर जोर दिया गया है.

दुर्घटना टालने वाले 15 रेलकर्मी सम्मानित

भोपाल,7 जनवरी . भोपाल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी द्वारा ड्यूटी के दौरान सतर्कता, सूझ-बूझ एवं त्वरित कार्यवाही से संभावित रेल दुर्घटनाओं को टालने वाले 15 रेलकर्मियों को दिनांक 7 जनवरी 2026 को सम्मानित किया गया.

इन कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र एवं संरक्षा नगद पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया. सम्मानित रेलकर्मियों में इटारसी के गुड्स ट्रेन मैनेजर राज कुमार पुरबिया, राहुल साहू, हरि प्रसाद अहिरवार, कमलेश कुमार अहिरवार, इटारसी के ट्रैकमेन कन्हैया लाल, विशाल थातिया, बीना के ट्रैकमेन शिवराज सिंह,

हेमराज अहिरवार, नर्मदापुरम के ट्रैकमेन गौरव कुमार, विदिशा के ट्रैकमेन अमित राजपूत, छनेरा के ट्रैकमेन सोहन लाल, अशोकनगर के प्वांट्समेन मनोज कुमार , बरखेड़ा के उप स्टेशन प्रबंधक शहजाद खान, चचोड़ा-बीना गंज के उप स्टेशन प्रबंधक राहुल कुमार मीना एवं व्यावरा राजगढ़ के प्वांट्समेन हरिओम जाटव शामिल हैं. इन रेलकर्मियों ने अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में रेल फ्रैक्चर, हॉट एक्सल, धुआं निकलते वैगन, ओएचई ट्रिप, क्रैक एवं अन्य असामान्य परिस्थितियों को समय रहते पहचान कर अधिकारियों को सूचित किया तथा ट्रेनों को सुरक्षित रूप से रोका.

उनकी सजगता एवं त्वरित निर्णय क्षमता से गंभीर दुर्घटनाओं को रोका जा सका, जिससे यात्रियों एवं रेलवे संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित हुई. इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी ने कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि रेलवे में संरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे कर्मी संगठन के लिए प्रेरणास्रोत हैं. वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे और कर्मचारियों के समर्पण की सराहना की.

आंखों देखी | विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ने इंदौर में मौके पर पहुंचकर किया वाटर ऑडिट

हर घर का पीने का पानी असुरक्षित : उमंग

विशेष संवाददाता

भोपाल, 7 जनवरी. मध्यप्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बुधवार को इंदौर के विभिन्न इलाकों में मौके पर पहुंचकर वाटर ऑडिट किया.

इस दौरान उन्होंने पानी के सैंपल लेकर प्रारंभिक जांच की, जिसमें उनके अनुसार शहर के अधिकांश क्षेत्रों में पेयजल अत्यधिक दूषित और पीने योग्य नहीं पाया गया. यह दौरा ऐसे समय पर हुआ है, जब भागीरथपुरा में कथित रूप से दूषित पानी पीने से 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि राज्य सरकार और नगर निगम पर जिम्मेदारी से बचने के आरोप लग रहे हैं. सिंघार ने कहा कि यह संकट केवल

भागीरथपुरा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा इंदौर सीवेज मिला पानी पीने को मजबूर है. उन्होंने कहा, 'जो काम प्रशासन को करना चाहिए था, वह आज विपक्ष को सड़कों पर उतरकर करना पड़ रहा है.' मदीना नगर में स्थानीय लोगों ने नए नल कनेक्शन, कथित बकाया और वार्षिक जल कर के नाम पर भारी वसूली तथा भुगतान न करने पर कनेक्शन काटने की धमकियों की शिकायत की, जबकि सप्लाई गंदे पानी की हो रही है.

खजराना क्षेत्र में नर्मदा का पानी बदबूदार और प्रदूषित पाया गया, जिसे सिंघार ने देश के सबसे स्वच्छ शहर कहलाने वाले इंदौर के लिए शर्मनाक बताया. भूरी टेकरी, इंदौर विधानसभा क्षेत्र-2, बर्फानी धाम और कनाडिया में भी नालियों के पास से गुजरती पाइपलाइनें और समान हालात सामने आए. नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया कि क्या सरकार और मौतों के बाद ही जागेगी और चेतावनी दी कि यदि तुरंत ठोस कदम और जवाबदेही तय नहीं की गई, तो कांग्रेस जन आंदोलन करेगी.

अब निगमायुक्त ने संभाली कमान

जबलपुर. नगर निगम की कार्यप्रणाली में इन दिनों पारदर्शिता और जवाबदेही की एक नई झलक देखने को मिल रही है। कागजी दावों से जगह अब निगम का काम जमीनी धरातल पर स्पष्ट रूप से नजर आने लगा है।

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
वेबसाइट: www.dhsgsu.edu.in
(NAAC A+ ग्रेड मान्यता प्राप्त केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रोग्रामों में प्रवेश 2026-27
स्नातक (यूजी) एवं स्नातकोत्तर (पीजी) प्रोग्रामों में प्रवेश लेने के लिए सीयूईटी-यूजी एवं सीयूईटी-पीजी में सीयूईटी अंक पाने के लिए पंजीयन हेतु पोर्टल नेशनल टेस्टिंग एजेंन्सी (एनटीए) द्वारा खोला गया है। इच्छुक एवं पात्र आवेदकों से अनुरोध है कि पंजीयन हेतु नीचे दी गई लिंक/वेबसाईट पर भ्रमण करें।

क्रं.	प्रोग्राम	लिंक/वेबसाईट	अंतिम तिथि
1.	स्नातक प्रोग्रामों के लिए	https://cuet.nta.nic.in/registration-for-cuetug-2026-is-live/	30.01.2026
2.	स्नातकोत्तर प्रोग्रामों के लिए	https://exams.nta.nic.in/registration-for-cuetpg-2026/	14.01.2026
पात्रता के लिए वेबसाईट www.dhsgsu.edu.in संपर्क फोन. 07582-297123 ईमेल: admission@dhsgsu.edu.in			

कुलसचिव

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा 3, इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स, रामगोपाल माहेश्वरी मार्ग, महाराणा प्रताप नगर, जोन-1, भोपाल से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि., इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स से मुद्रित. संपादक दिलीप झा*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-4939198, ईमेल-bhopalnav@gmail.com RNI Reg. No. 35046/56 डाक पंजीयन क्रमांक M.P/B.P.L/711/2012-14